

**PRESS RELEASE IN THE FORM OF NEWS ITEM ON THE PROPOSED
AMENDMENT OF ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS TOWN & COUNTRY
PLANNING REGULATION, 1994**

Andaman & Nicobar Administration has proposed to make amendments in the Andaman & Nicobar Town & Country Planning Regulation, 1994 published in the Official Gazette of A&N Administration vide Notification No.158 dated 19/12/1994 enabling the Administrator to carry out modification to the Master Plans including its characters, extent of land uses and standards of Population density. Accordingly, views, suggestions and comments are invited from all stakeholders upon the amendment proposed.

The amendment contemplated on the Andaman & Nicobar Town & Country Planning Regulation, 1994 has been published in the Daily Telegrams and other newspapers. The contents of the amendment is uploaded in the A&N Administration and APWD websites viz. www.andaman.gov.in and www.apwd.and.nic.in respectively. In addition, the copies of the proposed amendment is kept for display in the Town & Country Planning Unit, CE's Office, APWD, Port Blair for facilitating the general public.

It is requested that any objections/suggestions/comments on the amendment proposal may kindly be submitted to the Chief Engineer & Town Planner, Office of the Chief Engineer, APWD, Nirman Bhawan, Port Blair within 30 days from the date of publication of the Notification. The views can also be submitted by sending e-mail to tcpdtcp@gmail.com.

Chief Engineer & Town Planner

**PROPOSAL FOR AMENDMENT OF ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS
TOWN & COUNTRY PLANNING REGULATION, 1994**

Whereas, the Govt. of India promulgated & notified Andaman & Nicobar Town & Country Planning Regulation, 1994 (A&NITCP Regulation, 1994) (No. 07 of 1994) in the Gazette of India vide No. 61 dated 05/08/1994 which was again notified in the A&N Gazette vide No.158 dated 19/12/1994. Subsequently, the Administrator/Hon'ble Lt. Governor of Andaman & Nicobar Islands had formulated and notified the Andaman & Nicobar Town & Country Planning Rules, 2005 vide No. 283 dated 28/09/2005 by invoking powers to make the rules under Section-34 of A&NITCP Regulation, 1994.

And Whereas, two Master Plans viz. Master Plan for Port Blair Planning (Development) Area (PBPA) and Master Plan for Swaraj & Saheed Dweep were finalized and notified in the year 2012 and 2015 respectively under the provisions of A&NITCP Regulation, 1994.

Now, the Andaman & Nicobar Administration has proposed to make amendments in the Andaman & Nicobar Town & Country Planning Regulation, 1994 published in the Official Gazette of A & N Administration vide Notification No.158 dated 19/12/1994 enabling the Administrator to carry out modification to the Master Plans including its characters, extent of land uses and standards of Population density.

Accordingly, views, suggestions and comments are invited from all stakeholders upon the amendment proposed as below :-

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS
(Legislative Department)
New Delhi, the 2019

THE ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS TOWN AND COUNTRY PLANNING
(AMENDMENT) REGULATION, 2019

No..... of 2019

“Promulgated by the President in the Sixty Ninth year of the Republic of India as follows:-

A Regulation to amend the Andaman and Nicobar Islands Town & Country Planning Regulation, 1994

In exercise of powers conferred by Clause (1) of Article 240 of the Constitution, the President is pleased to promulgate the following amendment in the Regulation made by him”

1. Short title and commencement:-

- (i) The Regulation may be called Andaman & Nicobar Islands Town and Country Planning (Amendment) Regulation, 2019
- (ii) It extends to the whole of the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands
- (iii) It shall come into force from on such date the Administrator may, by notification in the Official Gazette, appoint.

(2) *Sub-section (1) and Sub-section (2) of Section 9 of the Principle Regulation shall be substituted as follows:-*

“(1) The Administrator may make any modification to the Master Plan, if he/she is of the opinion to do so in the interest of general public.

(2) The Central Government may, in the interest of security of the State or of the General Public make any modifications to the Master Plan.”

President of India

Secretary to Govt. of India

It is requested that any objections/suggestions/comments on the amendment proposal may kindly be submitted to the Chief Engineer & Town Planner, Office of the Chief Engineer, APWD, Nirman Bhawan, Port Blair within 30 days from the date of publication of the Notification. The views can also be submitted by sending e-mail to tcpdtcp@gmail.com.

Chief Engineer & Town Planner

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह नगर एवं ग्राम योजना विनियम 1994 में संशोधन के लिए प्रस्ताव

जबकि, भारत सरकार ने अण्डमान तथा निकोबार नगर एवं ग्राम योजना विनियम, 1994/अ.नि.ही.न.ग्रा.यो. विनियम, 1994) /संख्या 1994 का 07) को भारत के राजपत्र में दिनांक 05/08/1994 की संख्या 61 जिसे दोबारा अ. तथा. नि. राजपत्र में दिनांक 19/12/1994 की संख्या 158 में अधिसूचना प्रवर्तित किया है। उत्तरवर्ती, प्रशासक/माननीय उप-राज्यपाल, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह ने अण्डमान तथा निकोबार नगर एवं ग्राम योजना नियम, 2005 के दिनांक 28/09/2005 की संख्या 283 में प्रदत्त शक्तियों का आह्वान करते हुए, अ. तथा नि.द्वी.न.ग्रा.यो विनियम, 1994 की धारा-34 के अंतर्गत नियम बनाने को अधिसूचित करते हुए प्रवर्तित करते हैं ।

और जबकि, दो मास्टर प्लान अर्थात: पोर्ट ब्लेयर नियोजन (विकास) क्षेत्र (पी.बी.पी.ए) के लिए मास्टर प्लान तथा स्वराज तथा शहीद द्वीपों के लिए मास्टर प्लान को अंतिम रूप दे दिया और क्रमशः 2012 तथा 2015 के अ.ल.नि.द्वी.न.ग्रा.यो विनियम 1994 के प्रावधानों के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है ।

अब, अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन ने अं. तथा नि. प्रशासन की दिनांक 19/12/1994 की संख्या 158 के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित अण्डमान तथा निकोबार नगर एवं ग्राम योजना विनियम, 1994 में संशोधन का प्रस्ताव रखते हैं, ताकि प्रशासक को, मास्टर प्लान के उसके स्वरूप, भूमि उपयोग का विस्तार तथा जनसंख्या घनत्व के मानकों सहित संशोधन किया जा सके ।

तदनुसार, सभी हितधारकों से निम्नलिखित प्रस्तावित संशोधनों पर दृष्टिकोण, सुझाव तथा टिप्पणियाँ आमंत्रित करते हैं :-

विधि, न्याय तथा कम्पनी मामलों का मंत्रालय

(विधायी विभाग)

नई दिल्ली,.....2019

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह नगर एवं ग्राम योजना (संशोधन) विनियम, 2019

संख्या : 2019 का

“भारत गणराज के उनहत्तरवें वर्ष में राष्ट्रपति द्वारा प्रवर्तित निम्नलिखित अनुसार है :-

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह नगर एवं ग्राम योजना विनियम, 1994 में संशोधन के लिए एक विनियम है ।

संविधान के अनुच्छेद 240 के खण्ड (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति उनके द्वारा बनाए गए विनियम में निम्नलिखित संशोधन प्रवर्तित करते हैं”

1. लघु शीर्ष तथा आरंभ :-

- (i) इस विनियम को अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह नगर एवं ग्राम योजना (संशोधन) विनियम, 2019 कहा जाएगा ।
- (ii) यह, पूरे संघशासित प्रदेश अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के लिए विस्तारित होगा ।
- (iii) यह प्रशासक द्वारा शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियुक्त ऐसे तारीख से प्रभावी होगा ।

2. प्रधान विनियम की धारा 9 की उप-धारा(1) तथा उप-धारा (2) को निम्नलिखित अनुसार एवजी में रखा जाएगा :

“(1) प्रशासक, मास्टर प्लान में कोई भी संशोधन कर सकते हैं, यदि उनके राय में ऐसा करना आम लोगों के हित में है ।

(2) केन्द्र सरकार, राज्य की सुरक्षा या आम लोगों के हित में मास्टर प्लान में कोई भी संशोधन कर सकते हैं ।”

भारत के राष्ट्रपति

भारत सरकार के सचिव

उपरोक्त संशोधन के संबंध में कोई भी आपत्तियाँ या सुझाव को, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 (तीस) दिनों के भीतर लिखित में नगर योजनाकार (मुख्य अभियंता, अ.लो.नि.वि, अ.लो.नि.वि, निर्माण भवन, पोर्ट ब्लेयर) को प्रस्तुत कर सकते हैं। अपने सुझाव को tcpdtcp@gmail.com में भी भेजा जा सकता है ।

मुख्य अभियंता एवं नगर योजनाकार